



Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam

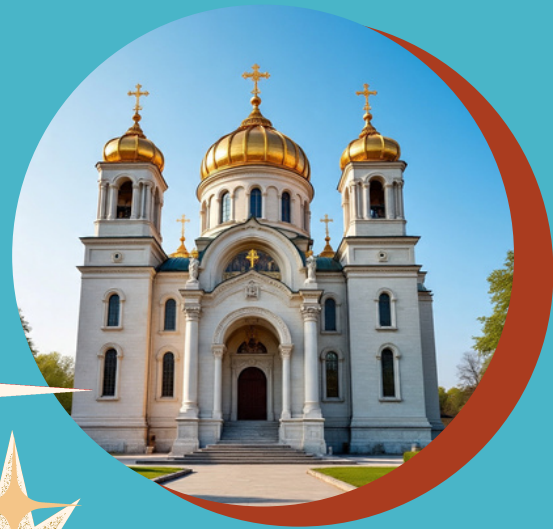


BANKING AND FINANCIAL AWARENESS

18 - 24 JAN 2026

3RD WEEK OF JANUARY

50+ MCQ
with detailed
explanation



- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement



Ques: What has been a major factor driving the recent surge in municipal bond issuances in India?

भारत में हाल के वर्षों में नगर निगम बॉन्ड जारी होने में तेज़ी का प्रमुख कारण क्या रहा है?

- A) Increase in foreign direct investment / प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि
- B) Fiscal incentives under AMRUT 2.0 / AMRUT 2.0 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन
- C) Mandatory bond issuance by municipalities / नगर निकायों के लिए बॉन्ड जारी करना अनिवार्य होना
- D) Reduction in interest rates by RBI / RBI द्वारा ब्याज दरों में कटौती
- E) Privatization of urban local bodies / शहरी स्थानीय निकायों का निजीकरण

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- By December of the current financial year, nine municipal bond issuances had already entered the market, indicating growing participation by urban local bodies.
- चालू वित्तीय वर्ष के दिसंबर तक नौ नगर निगम बॉन्ड बाजार में आ चुके थे, जो शहरी स्थानीय निकायों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।
- Data shows that the total outstanding value of municipal bonds stood at ₹3,783.9 crore as of September 30, 2025.
- आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर 2025 तक नगर निगम बॉन्ड का कुल बकाया मूल्य ₹3,783.9 करोड़ था।
- Nearly ₹1,000 crore was raised in the calendar year 2025 alone, marking the strongest single-year issuance so far.
- केवल वर्ष 2025 में ही लगभग ₹1,000 करोड़ जुटाए गए, जो अब तक का सबसे मजबूत एकलरहा। निर्गम वर्षीय-
- The recent momentum in municipal bond issuances is largely attributed to fiscal incentives provided under the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0 (AMRUT 2.0).
- नगर निगम बॉन्ड में हालिया गति का मुख्य कारण अटल मिशन फॉर रीजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 (AMRUT 2.0) के तहत दिए गए वित्तीय प्रोत्साहन हैं।
- Under AMRUT 2.0, a first-time municipal bond issuer can receive incentives of up to ₹13 crore for every ₹100 crore raised.
- AMRUT 2.0 के अंतर्गत, पहली बार बॉन्ड जारी करने वाले नगर निकाय को प्रत्येक ₹100 करोड़ जुटाने पर ₹13 करोड़ तक का प्रोत्साहन मिल सकता है।

Ques: Who has been appointed as the Chief Executive Officer (CEO) for the Health Insurance Ecosystem and Strategic Partnerships of the General Insurance Council?

जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Praveen Kumar / प्रवीण कुमार
- B) Anup Kumar Saha / अनुप कुमार साहा
- C) Karthikeyan Manickam / कार्तिकियन मणिकम
- D) Ida Liu / इडा लियू
- E) S Prakash / एस प्रकाश

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The General Insurance Council appointed S Prakash as the Chief Executive Officer for the Health Insurance Ecosystem and Strategic Partnerships.
- जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने एस प्रकाश को हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया।
- He replaced Praveen Kumar in this role.
- उन्होंने इस पद पर प्रवीण कुमार का स्थान लिया।
- The appointment aims to strengthen coordination and development in India's health insurance ecosystem.
- यह नियुक्ति भारत के हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम में समन्वय और विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है।

Ques: Who has been appointed as the chairperson of the high-level committee formed to formulate guidelines for assured payouts under the National Pension System (NPS)?

प्रश्न) प्रणाली पेंशन राष्ट्रीय :NPS) के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Ajay Tyagi / अजय त्यागी
- B) Supratim Bandyopadhyay / सुप्रतिम बंद्योपाध्याय

- C) M S Sahoo / एमसाहू .एस .
D) Ramesh Abhishek / रमेश अभिषेक
E) Urjit Patel / उर्जित पटेल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has constituted a high-level committee to formulate guidelines and regulations to enable a framework for assured payouts under the National Pension System (NPS).
- पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु दिशानिर्देश और विनियम बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।
- The committee is a 15-member body aimed at strengthening confidence and predictability in NPS payout mechanisms.
- यह समिति 15 सदस्यों वाली है, जिसका उद्देश्य NPS भुगतान प्रणाली में विश्वास और सुनिश्चितता को मजबूत करना है।
- The committee is chaired by M S Sahoo, former Chairperson of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI).
- इस समिति की अध्यक्षता दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) के पूर्व अध्यक्ष एम.एस. साहू रहे कर साहू .एस .

About PFRDA :

- Established : 2003
- HQ : New Delhi
- Chairman : Sivasubramanian Ramann

Ques: What restriction has the Reserve Bank of India imposed on resident Indians under the Foreign Exchange Management Regulations, 2026?
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस, 2026 के तहत RBI ने भारतीय निवासियों पर कौन-सी पाबंदी लगाई है?

- A) Ban on foreign investments / विदेशी निवेश पर प्रतिबंध
- B) Prohibition on issuing credit guarantees to NRIs / NRI को क्रेडिट गारंटी जारी करने पर रोक
- C) Restriction on remittances / रेमिटेंस पर रोक
- D) Ban on foreign borrowing / विदेशी उधार पर रोक
- E) Restriction on export payments / निर्यात भुगतान पर रोक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India issued the Foreign Exchange Management Regulations, 2026.
 - भारतीय रिज़र्व बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस, 2026 जारी किए।
 - Under these regulations, resident Indians are prohibited from issuing credit guarantees in favour of non-resident Indians (NRIs).
 - इन नियमों के तहत भारत में रहने वाले भारतीयों को गैर-निवासी भारतीयों (NRI) के पक्ष में क्रेडिट गारंटी जारी करने से रोका गया है।
 - RBI clarified that no person resident in India shall be a party to a guarantee if any other party to the guarantee is resident outside India.
 - RBI ने स्पष्ट किया कि यदि गारंटी का कोई भी पक्ष भारत के बाहर रहता है, तो भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति उस गारंटी का पक्ष नहीं बन सकता।
 - Resident Indians may act as surety or principal debtor only if the underlying transaction is permitted under foreign exchange law.
 - निवासी भारतीय तभी ज़मानती या प्रधान देनदार बन सकते हैं जब मूल लेन-देन विदेशी मुद्रा कानून के तहत अनुमत हो।
 - Both parties must also be eligible to lend or borrow under FEMA (Borrowing and Lending) Regulations, 2018.
 - दोनों पक्षों को FEMA (उधार लेना और देना) रेगुलेशंस, 2018 के तहत पात्र होना चाहिए।
 - These conditions do not apply to fully collateralised dealer banks, agents of foreign shipping or airline companies, and resident-to-resident guarantees.
 - ये शर्तें पूर्ण रूप से कोलैटरलाइज्ड डीलर बैंक, विदेशी शिपिंग या एयरलाइन कंपनी के एजेंट और निवासी-से-निवासी गारंटी पर लागू नहीं होतीं।
-

Ques: Which Indian financial institution became the first Indian issuer in 2026

to raise overseas debt through a dual-tranche, long-duration US dollar-denominated bond issue worth \$1 billion?

2026 में 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ड्यूलट्रॉच-, दीर्घ बॉन्ड मूल्यांकित-डॉलर अमेरिकी अवधि-बना कौन संस्थान भारतीय पहला वाला जुटाने ऋण से विदेशों कर जारी?

- A) State Bank of India (SBI) / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- B) Export-Import Bank of India (EXIM Bank) / भारतीय निर्यातबैंक आयात-
- C) Power Finance Corporation (PFC) / पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन
- D) National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) / राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण एवं विकास बैंक
- E) India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) / इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Export-Import Bank of India (EXIM Bank) accepted bids worth \$1 billion for its dual-tranche, long-duration US dollar-denominated bonds, marking the first overseas debt issuance by an Indian issuer in 2026.
- भारतीय निर्यात) बैंक आयात-EXIM Bank) ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ड्यूलट्रॉच-, दीर्घ-कीं स्वीकार बोलियाँ लिए के बॉन्ड कितमूल्यां-डॉलर अमेरिकी अवधि, जिससे यह 2026 में विदेशी ऋण जारी करने वाला पहला भारतीय जारीकर्ता बना।
- **The bond issue consists of two tranches:**
 - 10-year bond: \$500 million, coupon rate 5.00%, spread 85 basis points over the 10-year US Treasury yield.
 - 10-वर्षीय बॉन्ड :500 मिलियन डॉलर, कूपन दर 5.00%, 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड से 85 बेसिस पॉइंट अधिक।
 - 30-year bond: \$500 million, coupon rate 5.75%, spread 95 basis points over the 30-year US Treasury yield.
 - 30-वर्षीय बॉन्ड :500 मिलियन डॉलर, कूपन दर 5.75%, 30-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड से 95 बेसिस पॉइंट अधिक।
- The bonds are rated BBB– by Fitch Ratings, in line with EXIM Bank’s issuer rating.

- इन बॉन्ड्स को फिच रेटिंग्स द्वारा BBB- रेटिंग दी गई है, जो EXIM Bank की जारीकर्ता रेटिंग के अनुरूप है।
- The bonds will be listed on exchanges in Singapore, London and India.
- ये बॉन्ड सिंगापुर, लंदन और भारत के एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए जाएंगे।
- Proceeds from the issue will be used for general funding requirements, financing overseas investments, and funding the import of capital goods.
- इस बॉन्ड इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग सामान्य फंडिंग आवश्यकताओं, विदेशी निवेशों के लिए ऋण, तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात के वित्तपोषण में किया जाएगा।

Ques: What does the World Bank Group's 'Global Economic Prospects (January 2026)' report project for India's economic growth?

विश्व बैंक समूह की 'ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स जनवरी)2026)' रिपोर्ट भारत की आर्थिक वृद्धि के बारे में क्या अनुमान लगाती है?

- A) India's GDP growth is projected to decline to below 6% in FY26 / भारत की GDP वृद्धि FY26 में 6% से नीचे रहने का अनुमान
- B) India's GDP growth is projected at 7.2% in FY26, revised upward from earlier estimates / भारत की GDP वृद्धि FY26 में 7.2% रहने का अनुमान, जो पहले के अनुमान से अधिक है
- C) India's GDP growth is projected to remain unchanged at 6.3% in FY26 / भारत की GDP वृद्धि FY26 में 6.3% पर ही बनी रहने का अनुमान
- D) India's GDP growth is projected to accelerate to above 8% in FY27 / भारत की GDP वृद्धि FY27 में 8% से अधिक होने का अनुमान
- E) India's GDP growth is projected to stagnate with no moderation in FY27 / भारत की GDP वृद्धि FY27 में बिना किसी कमी के स्थिर रहने का अनुमान

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The World Bank Group released its flagship 'Global Economic Prospects (GEP): January 2026' report.
- विश्व बैंक समूह ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट 'ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स)GEP): जनवरी 2026' जारी की।
- The report has revised India's GDP growth projection for FY 2025–26 upward

to 7.2%, compared to the earlier estimate of 6.3% made in June 2025.

- रिपोर्ट में भारत की FY 2025–26 की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया है, जो जून 2025 में 6.3% आंका गया था।
- According to the report, India's economic growth is expected to moderate to 6.5% in FY27, lower than the previous estimate of 7.2%.
- रिपोर्ट के अनुसार, FY27 में भारत की आर्थिक वृद्धि घटकर 6.5% रहने की संभावना है, जो पहले 7.2% अनुमानित थी।
- These projections reflect both strong near-term economic momentum and expectations of gradual moderation in the medium term.
- ये अनुमान निकट अवधि में मजबूत आर्थिक गति और मध्यम अवधि में क्रमिक धीमेपन की संभावना को दर्शाते हैं।

Ques: How many cryptocurrency exchanges were registered with India's Financial Intelligence Unit (FIU-IND) during FY 2024–25, and under which law were crypto exchanges brought for AML–CTF compliance?

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) के साथ कितने क्रिप्टोकॉरेन्सी एक्सचेंज पंजीकृत हुए और उन्हें किस कानून के तहत AML–CTF अनुपालन में लाया गया?

- A) 49 exchanges – PMLA / 49 एक्सचेंज – PMLA
- B) 41 exchanges – IT Act / 41 एक्सचेंज – आईटी अधिनियम
- C) 32 exchanges – FEMA / 32 एक्सचेंज – FEMA
- D) 55 exchanges – RBI Act / 55 एक्सचेंज – RBI अधिनियम
- E) 60 exchanges – Companies Act / 60 एक्सचेंज – कंपनी अधिनियम

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- During FY 2024–25, a total of 49 cryptocurrency exchanges were registered with India's Financial Intelligence Unit (FIU-IND), most of them being domestic platforms.
- वित्त वर्ष 2024–25 में कुल 49 क्रिप्टोकॉरेन्सी एक्सचेंज भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) के साथ पंजीकृत हुए, जिनमें से अधिकांश घरेलू थे।
- As of March 2025, 45 onshore exchanges and 4 offshore exchanges were

registered with FIU-IND, allowing them to operate under India's regulatory and compliance framework.

- मार्च 2025 तक 45 ऑनशोर और 4 ऑफशोर एक्सचेंज FIU-IND के साथ पंजीकृत थे, जिससे वे भारत के अनुपालन ढांचे के तहत काम कर सकते हैं।
- During FY25, FIU-IND imposed penalties amounting to ₹28 crore on certain non-compliant crypto exchanges.
- वित्त वर्ष 2025 के दौरान FIU-IND ने कुछ गैर-अनुपालक क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ₹28 करोड़ का जुर्माना लगाया।
- In 2023, all crypto exchanges in India were brought under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), making them reporting entities for Anti-Money Laundering (AML) and Counter Terror Financing (CTF).
- वर्ष 2023 में भारत के सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत लाया गया, जिससे वे AML और CTF के लिए रिपोर्टिंग इकाइयाँ बन गईं।
- Cryptocurrencies are legally classified as Virtual Digital Assets (VDAs), and crypto trading platforms are designated as VDA Service Providers (VDA SPs).
- क्रिप्टोकॉरेसी को कानूनी रूप से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को VDA सर्विस प्रोवाइडर (VDA SPs) माना गया है।

Ques: Which bank has partnered with NPCI BHIM Services Limited (NBSL) to use its bank plugins for offering UPI services on its banking app?

किस बैंक ने अपने बैंकिंग ऐप पर UPI सेवाएँ प्रदान करने के लिए NPCI BHIM Services Limited (NBSL) के बैंक प्लगइन्स अपनाया को इन्स-?

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) Canara Bank / केनरा बैंक
- D) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Canara Bank will use NPCI BHIM Services' (NBSL) bank plugins to offer Unified Payments Interface (UPI) services on its banking payments app, Canara ai1Pe.

- केनरा बैंक अपने बैंकिंग भुगतान ऐप Canara ai1Pe पर UPI सेवाएँ प्रदान करने के लिए NPCI BHIM Services (NBSL) के बैंक प्लगकरेगा। उपयोग का इन्स-
- This partnership enables Canara Bank to integrate the latest UPI payment launches and feature upgrades within its app, similar to functionalities available on the BHIM app.
- इस साझेदारी के तहत केनरा बैंक अपने ऐप में BHIM ऐप जैसी नवीनतम UPI सुविधाएँ और फीचर अपग्रेड्स को एकीकृत कर सकेगा।
- Canara Bank is the first bank to adopt this technology-sharing approach from NBSL.
- केनरा बैंक NBSL द्वारा अपनाए गए इस टेक्नोलॉजी पहला वाला अपनाने को मॉडल शेयरिंग-है। बैंक
- In 2025, BHIM had presented a proof of concept for BHIM Vishwas, allowing banks to leverage BHIM's technology stack.
- वर्ष 2025 में BHIM ने 'BHIM विश्वास' के तहत एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था, जिससे बैंक BHIM की तकनीकी संरचना का उपयोग कर सकें।

Ques: Which organisation has been recognised by the Reserve Bank of India (RBI) as a Self-Regulatory Organisation (SRO) for all Authorised Dealers under the Omnibus SRO Framework in January 2026?

जनवरी 2026 में RBI के ओम्निबस SRO फ्रेमवर्क के तहत सभी अधिकृत डीलरों के लिए किस संगठन को स्व) संगठन नियामक-SRO) के रूप में मान्यता दी गई है?

- A) FIMMDA – Fixed Income Money Market & Derivatives Association / फिममडा
- B) FIDC – Finance Industry Development Council / फिडक
- C) FEDAI – Foreign Exchange Dealers' Association of India / फेडाई
- D) FACE – Fintech Association for Consumer Empowerment / फेस
- E) AMFI – Association of Mutual Funds in India / एम्फी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) submitted an application to the RBI under the Omnibus Framework for recognition of Self-Regulatory Organisations (SROs) for Regulated Entities.

- फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FEDAI) ने विनियमित संस्थाओं के लिए SRO की मान्यता हेतु RBI के ओम्निबस फ्रेमवर्क के तहत आवेदन किया था।
- After examining the application, RBI decided to recognise FEDAI as an SRO for all Authorised Dealers, considering that it has long functioned like an SRO through its rules governing member conduct.
- आवेदन की समीक्षा के बाद RBI ने FEDAI को सभी अधिकृत डीलरों के लिए SRO के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया, क्योंकि यह पहले से ही अपने सदस्यों के आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों के माध्यम से SRO की तरह कार्य कर रहा था।
- FEDAI has been granted one year to align its governance and operational framework with the Omnibus SRO Framework.
- FEDAI को अपने प्रशासनिक और परिचालन ढांचे को ओम्निबस SRO फ्रेमवर्क के अनुरूप करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया है।
- It must also extend its membership to all categories of Authorised Dealers during this period.
- इस अवधि में FEDAI को सभी श्रेणियों के अधिकृत डीलरों तक अपनी सदस्यता का विस्तार करना होगा।
- As of January 2026, RBI has recognised four SROs under the new Omnibus Framework:
 - FEDAI (Forex Authorised Dealers) – January 14, 2026
 - FIDC (NBFCs) – October 3, 2025
 - FIMMDA (Bonds & Derivatives Markets) – May 7, 2025
 - FACE (Fintech) – August 2024
- जनवरी 2026 तक RBI ने नए ओम्निबस फ्रेमवर्क के तहत चार SRO को मान्यता दी है : FEDAI, FIDC, FIMMDA और FACE।
- Apart from this, RBI-recognised SROs also exist in the microfinance sector (MFIN and Sa-Dhan), while SEBI recognises bodies like AMFI (Association of Mutual Funds in India), BSE, NSE, RAIN (Registrars Association of India), IVCA (Indian Venture and Alternate Capital Association) and others as SROs in capital markets.
- इसके अतिरिक्त, माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में MFIN और Sa-Dhan RBI-मान्यता प्राप्त SRO हैं, जबकि पूंजी बाजार में AMFI, BSE, NSE आदि SEBI द्वारा SRO के रूप में माने जाते हैं।

Ques: What is the focus of the fifth edition of NITI Aayog's Trade Watch Quarterly launched in New Delhi?

नई दिल्ली में लॉन्च किए गए नीति आयोग के ट्रेड वॉच क्वार्टरली के पाँचवें संस्करण का मुख्य फोकस क्या है?

- A) India's agricultural subsidies and WTO disputes / भारत की कृषि सब्सिडी और WTO विवाद
- B) Structural shifts in India's trade profile and export competitiveness / भारत की व्यापार संरचना में बदलाव और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता
- C) Impact of global inflation on India's domestic prices / वैश्विक मुद्रास्फीति का भारत की घरेलू कीमतों पर प्रभाव
- D) Bilateral trade agreements signed in FY 2025–26 / FY 2025–26 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय व्यापार समझौते
- E) Performance of public sector enterprises in exports / निर्यात में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- NITI Aayog launched the fifth edition of **Trade Watch Quarterly**, covering the first quarter (Q1) of FY 2025–26.
 - नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का पाँचवाँ संस्करण लॉन्च किया, जो FY 2025–26 की पहली तिमाही (Q1) को कवर करता है।
 - The report highlights emerging structural shifts in India's trade profile, including a rising share of technology-intensive exports and continued strength of services-led growth.
 - रिपोर्ट भारत की व्यापार संरचना में उभरते बदलावों को दर्शाती है, जिसमें प्रौद्योगिकी-शामिल वृद्धि वाली नेतृत्व के सेवाओं और हिस्सेदारी बढ़ती की निर्यात प्रधान
 - It also notes changes in import composition, reflecting deeper integration into Global Value Chains (GVCs).
 - इसमें आयात संरचना में बदलाव का भी उल्लेख है, जो वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVCs) में भारत के गहरे एकीकरण को दर्शाता है।
 - A special focus of the report is on the structure and competitiveness of India's exports, particularly automotive exports, their evolving composition, and India's position in global markets.
 - रिपोर्ट का विशेष फोकस भारत के निर्यात की संरचना और प्रतिस्पर्धात्मकता पर है, खासकर ऑटोमोटिव निर्यात, उनकी बदलती संरचना और वैश्विक बाजारों में भारत की स्थिति पर।
-

Ques: Which bank has received RBI and Karnataka Government approval to collect State government revenue through the Khajane-2 Integrated Financial Management System (IFMS)?

किस बैंक को खजाने-2 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) के माध्यम से राज्य सरकार के राजस्व संग्रह हेतु RBI और कर्नाटक सरकार की मंजूरी मिली है?

- A) Canara Bank / केनरा बैंक
- B) Karnataka Bank / कर्नाटक बैंक
- C) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- D) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- E) Indian Bank / इंडियन बैंक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Karnataka Bank has secured the necessary authorization from the Reserve Bank of India (RBI) and approval from the Department of Treasuries, Government of Karnataka.
- कर्नाटक बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और कर्नाटक सरकार के ट्रेजरी विभाग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त हुई है।
- This approval enables the bank to collect State government revenue receipts through the Khajane-2 Integrated Financial Management System (IFMS).
- इस मंजूरी के तहत बैंक खजाने-2 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) के माध्यम से राज्य सरकार की राजस्व रसीदें जमा कर सकेगा।
- With this enablement, Karnataka Bank can collect various State government taxes and fees from citizens of Karnataka using its Internet banking services.
- इस सुविधा के साथ कर्नाटक बैंक अपनी इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से कर्नाटक के नागरिकों से विभिन्न राज्य सरकारी कर और शुल्क एकत्र कर सकेगा।
- Karnataka Bank was established in 1924 and is headquartered in Mangaluru, Karnataka.
- कर्नाटक बैंक की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय मंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है।
- The CEO & Managing Director of Karnataka Bank is Raghavendra Srinivas Bhat, and its tagline is "Your Family Bank Across India."
- कर्नाटक बैंक के CEO एवं प्रबंध निदेशक राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट हैं और इसका टैगलाइन "Your Family Bank Across India" है।

Ques: Which international financial institutions jointly provided a USD 350 million loan to Piramal Finance Limited?

पिरामल फाइनेंस लिमिटेड को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने संयुक्त रूप से प्रदान किया?

- A) World Bank and IMF / विश्व बैंक और IMF
- B) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and ADB / AIIB और ADB
- C) International Finance Corporation (IFC) and Asian Development Bank (ADB) / IFC और ADB
- D) New Development Bank (NDB) and World Bank / NDB और विश्व बैंक
- E) European Investment Bank (EIB) and ADB / EIB और ADB

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Piramal Finance Limited has received a total loan of USD 350 million.
 - पिरामल फाइनेंस लिमिटेड को कुल 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ है।
 - The loan has been jointly provided by the International Finance Corporation (IFC) and the Asian Development Bank (ADB).
 - यह ऋण अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) और एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है।
 - Of the total amount, IFC has contributed USD 200 million, while ADB has provided USD 150 million.
 - कुल राशि में से IFC ने 200 मिलियन डॉलर और ADB ने 150 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है।
 - The loan has a tenure of five years.
 - इस ऋण की अवधि पाँच वर्ष है।
 - Piramal Finance Limited is headquartered in Mumbai.
 - पिरामल फाइनेंस लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
 - The Managing Director and CEO of the company is Jairam Sridharan.
 - कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) जयराम श्रीधरन हैं।
-

Ques: What major change did SEBI propose to ease liquidity strain for Foreign Portfolio Investors (FPIs)?

SEBI ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए तरलता दबाव कम करने हेतु कौन-सा प्रमुख बदलाव प्रस्तावित किया?

- A) Introduction of weekly settlement cycle / साप्ताहिक सेटलमेंट चक्र की शुरुआत
- B) Same-day fund netting of buy and sell obligations / खरीद-बिक्री दायित्वों की उसी दिन फंड नेटिंग
- C) Reduction in securities transaction tax / सिक्क्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में कटौती
- D) Mandatory escrow funding for FPIs / FPIs के लिए अनिवार्य एस्करो फंडिंग
- E) Extension of trading hours for FPIs / FPIs के लिए ट्रेडिंग समय बढ़ाना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- SEBI proposed allowing Foreign Portfolio Investors (FPIs) to offset their purchase and sale obligations within the same trading day.
- SEBI ने FPIs को एक ही ट्रेडिंग दिन में अपनी खरीद और बिक्री की देनदारियों को समायोजित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया।
- This proposal aims to replace the existing system where settlements are required on a gross basis.
- यह प्रस्ताव मौजूदा ग्राँस बेसिस सेटलमेंट प्रणाली को बदलने के लिए है।
- At present, FPIs must separately fund every buy order and deliver securities for every sell order, even if both occur on the same day.
- वर्तमान में, FPIs को हर खरीद ऑर्डर के लिए अलग से फंडिंग करनी होती है और हर बिक्री ऑर्डर के लिए सिक्क्योरिटीज डिलीवर करनी होती हैं, भले ही दोनों लेनदेन एक ही दिन हों।
- Even when the value of buy and sell transactions is equal, the investor must arrange full funds for the purchase leg.
- भले ही खरीद और बिक्री की राशि समान हो, निवेशक को खरीद के लिए पूरी फंडिंग का इंतज़ाम करना पड़ता है।
- For example, an investor buying and selling shares worth ₹100 crore each still needs to arrange ₹100 crore in funds.
- उदाहरण के तौर पर, ₹100 करोड़ के शेयर खरीदने और बेचने वाले निवेशक को फिर भी ₹100 करोड़ की फंडिंग करनी होती है।
- The proposed same-day fund netting will reduce liquidity pressure and improve capital efficiency for FPIs.

- प्रस्तावित उसी दिन फंड नेटिंग से FPIs पर तरलता दबाव कम होगा और पूंजी दक्षता बढ़ेगी।

Ques: Why is JPMorgan Chase replacing Goldman Sachs as the issuer of the Apple Card?

जेपीमॉर्गन चेज़, एप्पल कार्ड के जारीकर्ता के रूप में गोल्डमैन सैक्स की जगह क्यों ले रहा है?

- A) To exit the premium digital credit card segment / प्रीमियम डिजिटल क्रेडिट कार्ड से बाहर निकलने के लिए
- B) To transfer Apple Card operations to a fintech company / एप्पल कार्ड संचालन को किसी फिनटेक कंपनी को सौंपने के लिए
- C) To strengthen JPMorgan's consumer banking business while Goldman scales back retail finance / जेपीमॉर्गन के उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार को मजबूत करने और गोल्डमैन के रिटेल फाइनेंस से पीछे हटने के लिए
- D) Due to Apple ending its credit card partnership / एप्पल द्वारा क्रेडिट कार्ड साझेदारी समाप्त करने के कारण
- E) Because of regulatory penalties on Goldman Sachs / गोल्डमैन सैक्स पर नियामकीय जुर्माने के कारण

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- JPMorgan Chase will replace Goldman Sachs as the issuer of the Apple Card.
- जेपीमॉर्गन चेज़, एप्पल कार्ड के जारीकर्ता के रूप में गोल्डमैन सैक्स की जगह लेगा।
- The move will transfer over \$20 billion in Apple Card credit balances to JPMorgan's platform.
- इस बदलाव से एप्पल कार्ड के 20 अरब डॉलर से अधिक के क्रेडिट बैलेंस जेपीमॉर्गन के प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित होंगे।
- For JPMorgan Chase, the deal strengthens its credit card and consumer banking business.
- जेपीमॉर्गन चेज़ के लिए यह सौदा उसके क्रेडिट कार्ड और उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार को मजबूत करता है।
- It also expands JPMorgan's presence in the premium digital credit card segment.

- इससे प्रीमियम डिजिटल क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में जेपीमॉर्गन की मौजूदगी बढ़ेगी।
- For Goldman Sachs, the move aligns with its strategy to scale back consumer finance operations.
- गोल्डमैन सैक्स के लिए यह कदम उसके उपभोक्ता वित्त को कारोबार (फाइनेंस कंज्यूमर) है। अनुरूप के रणनीति की करने सीमित
- It reflects Goldman Sachs' continued retreat from retail-focused ventures such as co-branded credit cards.
- यह को पीछे लगातार के सैक्स गोल्डमैन से मोंउपक्र केंद्रित-रिटेल जैसे कार्ड क्रेडिट ब्रांडेड- है। दर्शाता को हटने
- The transaction is subject to regulatory approvals and is expected to be completed in about two years.
- यह लेनदेन नियामकीय मंजूरियों पर निर्भर है और लगभग दो वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है।

Ques: What is the key provision introduced under the RBI Integrated Ombudsman Scheme, 2026 to strengthen customer grievance redressal?
RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, 2026 के तहत ग्राहक शिकायत निवारण को मज़बूत करने के लिए कौन-सा प्रमुख प्रावधान किया गया है?

- A) Manual review of complaints by RBI offices / RBI कार्यालयों द्वारा शिकायतों की मैनुअल समीक्षा
- B) Auto-transfer of unresolved complaints to Internal Ombudsman / अनसुलझी शिकायतों का इंटरनल ओम्बड्समैन को स्वतः ट्रांसफर
- C) Closure of complaints by the same bank branch / उसी बैंक शाखा द्वारा शिकायत निपटान
- D) Extension of complaint resolution time to 60 days / शिकायत निवारण समय 60 दिन करना
- E) Limiting the scheme only to public sector banks / योजना को केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तक सीमित करना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- To strengthen customer protection in the financial system, the Reserve Bank

of India issued new directions on grievance redressal.

- वित्तीय प्रणाली में ग्राहक संरक्षण को मज़बूत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिकायत निवारण पर नए निर्देश जारी किए।

- RBI issued Master Circular–1 under the Integrated Ombudsman Scheme, 2026. The revised scheme will come into force from 1 July 2026.

- RBI ने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, 2026 के तहत मास्टर सर्कुलर-1 जारी किया। संशोधित योजना 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।

- Under the revised norms, banks and eligible NBFCs must automatically transfer unresolved complaints to their Internal Ombudsman.

- नए नियमों के तहत बैंकों और पात्र NBFCs को अनसुलझी शिकायतें अपने इंटरनल ओम्बड्समैन को स्वतः ट्रांसफर करनी होंगी।

- This provision ensures that the final decision is communicated to customers within 30 days of receipt of the complaint.

- यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि शिकायत मिलने के 30 दिनों के भीतर ग्राहक को अंतिम निर्णय बताया जाए।

- RBI has mandated that banks and eligible NBFCs establish a fully automated Complaint Management System (CMS).

- RBI ने बैंकों और पात्र NBFCs के लिए पूरी तरह ऑटोमेटेड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) अनिवार्य किया है।

- The CMS must allow seamless access to the Internal Ombudsman (IO) and Deputy Internal Ombudsman (DIO).

- CMS से इंटरनल ओम्बड्समैन (IO) और डिप्टी इंटरनल ओम्बड्समैन (DIO) तक आसानी से पहुँच होनी चाहिए।

- For complaints where RBI, NPCI, or card network rules prescribe timelines, the IO must be given at least 10 days for review.

- जिन शिकायतों में RBI, NPCI या कार्ड नेटवर्क नियमों में समयसीमा तय है, उनमें IO को समीक्षा के लिए कम से कम 10 दिन मिलेंगे।

- For all other complaints, a 20-day timeline from the date of receipt applies for IO review.

- अन्य सभी शिकायतों के लिए, शिकायत प्राप्त होने की तारीख से IO समीक्षा हेतु 20 दिन की समयसीमा होगी।

- Banks must classify complaints into three categories within the CMS: fully resolved, partially resolved, and wholly rejected.

- बैंकों को CMS में शिकायतों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना होगा: पूरी तरह सुलझी, आंशिक रूप से सुलझी, और पूरी तरह अस्वीकृत।

- Only partially resolved or wholly rejected complaints will be transferred to the Internal Ombudsman.

- केवल आंशिक रूप से सुलझी या पूरी तरह अस्वीकृत शिकायतें ही इंटरनल ओम्बड्समैन को

भेजी जाएँगी।

- RBI clarified that the same branch or unit cannot close a complaint, whether resolved or rejected, to avoid conflict of interest and ensure fairness.
- RBI ने स्पष्ट किया कि हितों के टकराव से बचने और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कोई भी शाखा या यूनिट स्वयं शिकायत बंद नहीं कर सकती।
- These norms apply to banks having 10 or more outlets in India as on 31 March 2025.
- ये नियम 31 मार्च 2025 तक भारत में 10 या उससे अधिक आउटलेट वाले बैंकों पर लागू होंगे।
- For NBFCs, the rules apply to deposit-taking NBFCs with 10 or more branches and non-deposit-taking NBFCs having assets of ₹5,000 crore or more with a public customer interface.
- NBFCs के मामले में, ये नियम 10 या उससे अधिक शाखाओं वाली डिपॉजिट-टेकिंग NBFCs और ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक एसेट वाली नॉन-डिपॉजिट-टेकिंग NBFCs पर लागू होंगे, जिनका सार्वजनिक ग्राहक इंटरफेस है।

Ques: What is the key objective behind Amazon Pay launching fixed deposit (FD) services on its fintech app?

अमेज़न पे ने अपने फिनटेक ऐप पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) सेवाएँ शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) To offer cryptocurrency-based investments / क्रिप्टोकॉरेन्सी आधारित निवेश प्रदान करना
- B) To expand into fixed-income investment products / फिक्स्ड निवेश इनकम-कर विस्तार में उत्पादोंना
- C) To replace traditional bank fixed deposits / पारंपरिक बैंक एफडी को समाप्त करना
- D) To provide unsecured personal loans / असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना
- E) To act as a full-fledged commercial bank / पूर्ण वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Amazon Pay has launched fixed deposit (FD) services on its fintech app as

part of its expansion into fixed-income assets.

- अमेज़न पे ने फिक्स्ड पर ऐप फिनटेक अपने तहत के विस्तार में परिसंपत्तियों इनकम-डिपॉजिट (FD) सेवाएँ शुरू की हैं।
- The FD offerings provide interest rates of up to 8%.
- इन एफडी पर 8% तक की ब्याज दर उपलब्ध कराई जा रही है।
- Amazon Pay has partnered with two NBFCs—Shriram Finance and Bajaj Finance—and five banks.
- अमेज़न पे ने दो एनबीएफसी—श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस—तथा पाँच बैंकों के साथ साझेदारी की है।
- The partner banks include Shivalik Small Finance Bank, Suryoday Small Finance Bank, South Indian Bank, Slice, and Utkarsh Small Finance Bank.
- साझेदार बैंकों में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्लाइस और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं।
- Users can start investing in FDs with a minimum amount of ₹1,000 without opening separate bank accounts with each institution.
- उपयोगकर्ता मात्र ₹1,000 से एफडी में निवेश शुरू कर सकते हैं और अलग में बैंकों अलग-होती। नहीं आवश्यकता की खोलने खाते
- Deposits made through the platform are insured up to ₹5 lakh per depositor per bank under DICGC rules.
- प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए गए जमा DICGC नियमों के तहत प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता ₹5 लाख तक बीमित हैं।

Ques: What was the key outcome of Bajaj Finserv's acquisition of Allianz SE's stake in its insurance businesses?

बजाज फिनसर्व द्वारा अपनी बीमा कंपनियों में एलियांज़ SE की हिस्सेदारी अधिग्रहण का प्रमुख परिणाम क्या रहा?

- A) Complete exit of Bajaj Group from insurance business / बजाज समूह का बीमा कारोबार से पूर्ण रूप से बाहर निकलना
- B) Reduction of Bajaj Finserv's ownership below majority level / बजाज फिनसर्व की हिस्सेदारी बहुमत से नीचे आना
- C) Increase in Bajaj Group's ownership to 97% with full management control / बजाज समूह की हिस्सेदारी बढ़कर 97% होना और पूर्ण प्रबंधन नियंत्रण मिलना
- D) Merger of Bajaj General Insurance and Bajaj Life Insurance / बजाज जनरल इंश्योरेंस और बजाज लाइफ इंश्योरेंस का विलय
- E) Listing of Allianz SE as a majority partner in India / एलियांज़ SE का भारत में बहुमत भागीदार बनना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Bajaj Finserv, along with Bajaj Holdings & Investment Limited and Jamnalal Sons Private Limited, has completed the acquisition of Allianz SE's 23% stake in its insurance subsidiaries.
- बजाज फिनसर्व ने बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड तथा जमनालाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर अपनी बीमा सहायक कंपनियों में एलियांज़ SE की 23% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया है।
- The acquisition involved Bajaj General Insurance and Bajaj Life Insurance.
- यह अधिग्रहण बजाज जनरल इंश्योरेंस और बजाज लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित है।
- The transaction value was ₹12,190 crore for Bajaj General Insurance and ₹9,200 crore for Bajaj Life Insurance.
- इस लेनदेन में बजाज जनरल इंश्योरेंस के लिए ₹12,190 करोड़ और बजाज लाइफ इंश्योरेंस के लिए ₹9,200 करोड़ का भुगतान किया गया।
- The total consideration for the acquisition amounted to ₹21,390 crore.
- अधिग्रहण के लिए कुल भुगतान राशि ₹21,390 करोड़ रही।
- Post-acquisition, Bajaj Group's ownership increased from 74% to 97%.
- अधिग्रहण के बाद बजाज समूह की हिस्सेदारी 74% से बढ़कर 97% हो गई।
- Bajaj Finserv now holds a 75.01% stake, giving it complete management control over the insurance businesses.
- बजाज फिनसर्व के पास अब 75.01% हिस्सेदारी है, जिससे उसे बीमा व्यवसायों पर पूर्ण प्रबंधन नियंत्रण प्राप्त हो गया है।

Ques: Who has been appointed as the Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of ICICI Bank Limited for a two-year tenure starting October 04, 2026?

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में 04 अक्टूबर 2026 से दो वर्ष के कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Uday Kotak / उदय कोटक
- B) Shikha Sharma / शिखा शर्मा
- C) Sandeep Bakshi / संदीप बख्शी

- D) Chanda Kochhar / चंदा कोचर
E) N. S. Kannan / एनकन्नन .एस .

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Sandeep Bakshi has been appointed as the MD and CEO of ICICI Bank Limited for a two-year term.
- संदीप बख्शी को आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- His tenure will be effective from October 04, 2026 to October 03, 2028.
- उनका कार्यकाल 04 अक्टूबर 2026 से 03 अक्टूबर 2028 तक होगा।
- Bakshi was first appointed as MD and CEO of ICICI Bank in October 2018.
- संदीप बख्शी को पहली बार अक्टूबर 2018 में आईसीआईसीआई बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया था।
- His term was subsequently extended until October 2026 before the current reappointment.
- इसके बाद उनके कार्यकाल को अक्टूबर 2026 तक बढ़ाया गया था।

About ICICI Bank :

- Established : 1994
 - HQ : Mumbai, Maharashtra
 - CEO & MD : Sandeep Bakhshi
 - Tagline : Hum Hai Na, Khayal Apka
-

Ques: Which bank won the 'Best Fintech & DPI Adoption' award at the 21st Indian Banks' Association (IBA) Banking Technology Awards 2026, and where was the event held?

21वें इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवॉर्ड्स 2026 में 'बेस्ट फिनटेक एवं DPI अपनाने' श्रेणी का पुरस्कार किस बैंक ने जीता और यह समारोह कहाँ आयोजित हुआ?

- A) State Bank of India – New Delhi / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – नई दिल्ली
B) HDFC Bank – Bengaluru / एचडीएफसी बैंक – बेंगलुरु

- C) Canara Bank – Chennai / केनरा बैंक – चेन्नई
D) ICICI Bank – Hyderabad / आईसीआईसीआई बैंक – हैदराबाद
E) Karnataka Bank – Mumbai / कर्नाटक बैंक – मुंबई

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Karnataka Bank won the 'Best Fintech & DPI Adoption' award.
 - कर्नाटक बैंक ने 'बेस्ट फिनटेक एवं DPI एडॉप्शन' श्रेणी का पुरस्कार जीता।
 - The award was conferred at the 21st Indian Banks' Association (IBA) Banking Technology Awards 2026.
 - यह पुरस्कार 21वें इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवॉर्ड्स 2026 में प्रदान किया गया।
 - The award ceremony was held in Mumbai.
 - यह पुरस्कार समारोह मुंबई में आयोजित हुआ।
 - The recognition highlights Karnataka Bank's effective adoption of FinTech innovations and Digital Public Infrastructure (DPI) in banking services.
 - यह सम्मान बैंकिंग सेवाओं में फिनटेक नवाचारों और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को प्रभावी रूप से अपनाने में कर्नाटक बैंक की उपलब्धियों को दर्शाता है।
-

Ques: Bank of Baroda has signed an MoU with which institution to boost infrastructure financing?

इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस संस्था के साथ MoU किया है?

- A) NABARD / नाबार्ड
B) SIDBI / सिडबी
C) IIFCL / आईआईएफसीएल
D) NHB / एनएचबी
E) EXIM Bank / एक्सिम बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Bank of Baroda signed a Memorandum of Understanding with India Infrastructure Finance Company Ltd (IIFCL) to collaborate on infrastructure financing.
- बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए।
- The partnership will facilitate joint lending and loan syndication for a wide range of infrastructure projects across India.
- यह साझेदारी देशभर में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए संयुक्त ऋण और लोन सिंडिकेशन को बढ़ावा देगी।
- The objective is to accelerate infrastructure development and support long-term economic growth.
- इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देना और दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को समर्थन देना है।
- IIFCL will provide sectoral expertise, while Bank of Baroda will contribute its banking and credit capabilities.
- IIFCL अपने क्षेत्रीय अनुभव का उपयोग करेगा, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी बैंकिंग और क्रेडिट क्षमताएँ प्रदान करेगा।

About IIFCL :

- Established: 2006
- Headquarters: New Delhi
- Managing Director: Shri Palash Srivastava

Ques: In which year did Public Sector Banks launch a Credit Assessment Model based on digital footprints for MSMEs?

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एमएसएमई के लिए डिजिटल फुटप्रिंट आधारित क्रेडिट असेसमेंट मॉडल किस वर्ष लॉन्च किया?

- A) 2022
- B) 2023
- C) 2024
- D) 2025
- E) 2026

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Public Sector Banks launched a Credit Assessment Model based on digital footprints for MSMEs in 2025.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025 में एमएसएमई के लिए डिजिटल फुटप्रिंट आधारित क्रेडिट असेसमेंट मॉडल शुरू किया।
- Between 1 April and 31 December 2025, more than 3.96 lakh MSME loan applications amounting to over ₹52,300 crore were sanctioned under digital credit underwriting programmes.
- 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 के बीच, डिजिटल क्रेडिट अंडरराइटिंग कार्यक्रमों के तहत 3.96 लाख से अधिक एमएसएमई ऋण आवेदन, ₹52,300 करोड़ से अधिक की राशि के लिए स्वीकृत किए गए।
- The model uses digitally fetched and verifiable data to enable automated MSME loan appraisal and model-based limit assessment for both Existing-to-Bank (ETB) and New-to-Bank (NTB) borrowers.
- यह मॉडल डिजिटल रूप से प्राप्त और सत्यापन योग्य डेटा का उपयोग कर ETB और NTB दोनों प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए स्वचालित ऋण मूल्यांकन करता है।
- Digital footprints used include KYC authentication, mobile & email verification, GST data analysis, bank statement analysis via Account Aggregator, ITR verification, Credit Information Companies (CICs) data, and fraud checks.
- डिजिटल फुटप्रिंट में केवाईसी प्रमाणीकरण, मोबाइल व ईमेल सत्यापन, जीएसटी डेटा विश्लेषण, अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से बैंक स्टेटमेंट विश्लेषण, आईटीआर सत्यापन, क्रेडिट सूचना कंपनियों का डेटा और धोखाधड़ी जांच शामिल हैं।
- Benefits to MSMEs include online application from anywhere, reduced paperwork and branch visits, instant in-principle sanction, faster turnaround time, objective credit decisions, and integration with CGTMSE credit guarantee schemes.
- एमएसएमई को कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन, कम कागजी कार्रवाई, कम शाखा विज़िट, त्वरित इनस्वीकृति प्रिंसिपल-, कम समय में निर्णय और CGTMSE जैसी क्रेडिट गारंटी योजनाओं का एकीकरण का लाभ मिलता है।
- Loan applications are sourced through an end-to-end digital journey on the Jan Samarth Portal.
- ऋण आवेदन जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से एंड जाते किए प्राप्त से प्रक्रिया डिजिटल एंड-टू-हैं।

Ques: The World Bank approved a USD 286 million loan for which programme in India?

विश्व बैंक ने भारत में किस कार्यक्रम के लिए 286 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है?

- A) National Health Mission (NHM) / राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- B) Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission / आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन
- C) West Bengal Health System Reform Program (WBHSRP) / पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम
- D) National Digital Health Mission / राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- E) Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana / प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The World Bank approved a loan of USD 286 million for the West Bengal Health System Reform Program (WBHSRP).
 - विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम (WBHSRP) के लिए 286 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया।
 - The loan is provided through the World Bank's financing arm, the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).
 - यह ऋण विश्व बैंक की वित्तीय इकाई इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) के माध्यम से दिया गया है।
 - The loan has a tenure of 16.5 years with a grace period of 3 years.
 - ऋण की अवधि 16.5 वर्ष है, जिसमें 3 वर्ष की ग्रेस पीरियड शामिल है।
 - The programme aims to strengthen and reform the health system in West Bengal.
 - इस कार्यक्रम का उद्देश्य पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ और सुधारना है।
-

Ques: The Union Cabinet approved ₹5,000 crore equity support to which institution?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता किस संस्था को दी है?

- A) NABARD / नाबार्ड
- B) SIDBI / सिडबी
- C) RBI / आरबीआई
- D) EXIM Bank / एक्ज़िम बैंक
- E) NHB / एनएचबी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Union Cabinet approved equity support of ₹5,000 crore to the Small Industries Development Bank of India (SIDBI).
 - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) को ₹5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता को मंजूरी दी है।
 - The decision was taken under the chairmanship of Prime Minister Shri Narendra Modi.
 - यह निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया।
 - The equity will be infused by the Department of Financial Services (DFS) in three tranches.
 - यह इक्विटी वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा तीन चरणों में डाली जाएगी।
 - ₹3,000 crore will be infused in FY 2025–26, while ₹1,000 crore each will be provided in FY 2026–27 and FY 2027–28.
 - ₹3,000 करोड़ वित्त वर्ष 2025–26 में तथा ₹1,000–₹1,000 करोड़ वित्त वर्ष 2026–27 और 2027–28 में दिए जाएंगे।
 - The move will enhance SIDBI's lending capacity, improve credit flow to MSMEs, and help maintain a healthy CRAR.
 - इससे SIDBI की ऋण क्षमता बढ़ेगी, MSMEs को ऋण प्रवाह बेहतर होगा और CRAR संतुलित बना रहेगा।
-

**Ques: Which UN body projected India's GDP growth at 7.2% for FY 2025–26?
FY 2025–26 के लिए भारत की GDP वृद्धि 7.2% किस संयुक्त राष्ट्र निकाय ने अनुमानित की?**

- A) UNDP / यूएनडीपी
- B) IMF / आईएमएफ
- C) UN DESA / यूएन DESA
- D) World Bank / विश्व बैंक
- E) WTO / डब्ल्यूटीओ

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) projected India's GDP growth at 7.2% for the fiscal year 2025–26.
- संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए भारत की GDP वृद्धि 7.2% रहने का अनुमान लगाया है।
- This projection is slightly lower than the Indian government's estimate of 7.4% for FY 2025–26.
- यह अनुमान भारत सरकार द्वारा लगाए गए 7.4% के अनुमान से थोड़ा कम है।
- UN DESA stated that strong domestic consumption and public investment are expected to offset the impact of global trade tensions and tariffs.
- UN DESA के अनुसार, मजबूत घरेलू उपभोग और सार्वजनिक निवेश वैश्विक व्यापार तनाव और टैरिफ के प्रभाव को काफी हद तक संतुलित करेंगे।
- The projection was mentioned in the UN DESA report titled *World Economic Situation and Prospects*.
- यह अनुमान UN DESA की *World Economic Situation and Prospects* रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।
- India is expected to continue as one of the fastest-growing major economies in the world.
- भारत के विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बने रहने की उम्मीद जताई गई है।

Ques: Which institution has sanctioned a USD 22.5 million loan to Swarna Solar Limited for developing a 100 MW solar power project in Zambia?

स्वर्णा सोलर लिमिटेड को जाम्बिया में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए 22.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किस संस्था ने स्वीकृत किया है?

- A) Asian Development Bank (ADB) / एशियाई विकास बैंक
- B) International Finance Corporation (IFC) / अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम
- C) IREDA Global Green Energy Finance IFSC Limited (IGGEFIL) / इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड
- D) World Bank / विश्व बैंक
- E) New Development Bank (NDB) / न्यू डेवलपमेंट बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- IREDA Global Green Energy Finance IFSC Limited (IGGEFIL) has sanctioned a USD 22.5 million loan to Swarna Solar Limited.
- इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड (IGGEFIL) ने स्वर्णा सोलर लिमिटेड को 22.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है।
- The loan is for developing a 100 MW photovoltaic (PV) solar power project in Serenje District, Central Province of Zambia.
- यह ऋण जाम्बिया के सेंट्रल प्रांत के सेरेनजे जिले में 100 मेगावाट फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए है।
- This sanction marks IGGEFIL's first international loan since its incorporation.
- यह स्वीकृति IGGEFIL के गठन के बाद दिया गया पहला अंतरराष्ट्रीय ऋण है।
- IGGEFIL is incorporated at Gujarat International Finance TecCity (GIFT City), Gandhinagar, Gujarat.
- IGGEFIL का पंजीकरण गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी-GIFT सिटी(, गांधीनगर, गुजरात में है।

Ques: Indian Army has renewed its MoU for banking and insurance services till 2029 with which bank?

भारतीय सेना ने 2029 तक बैंकिंग और बीमा सेवाओं के लिए किस बैंक के साथ MoU नवीनीकृत किया है?

- A) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

- B) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- C) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- D) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Indian Army and HDFC Bank have renewed their Memorandum of Understanding (MoU) for another three years, extending it till 2029.
 - भारतीय सेना और HDFC बैंक ने अपने समझौता ज्ञापन (MoU) को अगले तीन वर्षों के लिए, यानी 2029 तक नवीनीकृत किया है।
 - The MoU aims to provide banking services and Personal Accident Insurance coverage to serving and retired Army personnel.
 - इस MoU का उद्देश्य सेवारत और सेवानिवृत्त सेना कर्मियों को बैंकिंग सेवाएँ और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना है।
 - The agreement includes an enhanced Personal Accident Insurance cover of ₹1 crore for serving personnel, including Agniveers and pensioners.
 - इस समझौते में अग्निवीरों और पेंशनरों सहित सेवारत कर्मियों के लिए ₹1 करोड़ का उन्नत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज शामिल है।
 - An Air Accident Insurance cover of ₹1 crore is also provided under the MoU.
 - MoU के तहत ₹1 करोड़ का एयर दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान किया गया है।
 - Additional benefits include a child education cover of ₹5 lakh and a girl child marriage cover of ₹5 lakh.
 - अतिरिक्त लाभों में ₹5 लाख की बाल शिक्षा सहायता और ₹5 लाख की कन्या विवाह सहायता शामिल है।
-

Ques: RBI has approved the re-appointment of whom as Whole-Time Director of HDFC Bank?

आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है?

- A) Sashidhar Jagdishan / सशिधर जगदीशन
- B) Kaizad Bharucha / काइज़ाद भरूचा

- C) Aditya Puri / आदित्य पुरी
D) Shyam Srinivasan / श्याम श्रीनिवासन
E) Uday Kotak / उदय कोटक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) approved the re-appointment of Kaizad Bharucha as Whole-Time Director (Deputy Managing Director) of HDFC Bank.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने काइज़ाद भरूचा को एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक (डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर) के रूप में पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दी।
- The approval was communicated by RBI on 20 January 2026.
- यह स्वीकृति आरबीआई द्वारा 20 जनवरी 2026 को दी गई।
- His re-appointment will be for a further period of three years starting from 19 April 2026.
- उनकी पुनर्नियुक्ति 19 अप्रैल 2026 से अगले तीन वर्षों के लिए प्रभावी होगी।
- HDFC Bank disclosed this information through a regulatory filing.
- एचडीएफसी बैंक ने इस निर्णय की जानकारी नियामक फाइलिंग के माध्यम से दी।
- After the announcement, HDFC Bank shares closed at ₹931.15 on BSE, registering a rise of 0.38%.
- घोषणा के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर बीएसई पर ₹931.15 पर बंद हुए, जिसमें 0.38% की बढ़त दर्ज की गई।

Ques: State Bank of India (SBI) signed an MoU with which state government to extend enhanced benefits under the Corporate Salary Package for State PSU employees?

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों के लिए कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के तहत बढ़े हुए लाभ देने हेतु किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) Government of Karnataka / कर्नाटक सरकार
B) Government of Kerala / केरल सरकार
C) Government of Tamil Nadu / तमिलनाडु सरकार
D) Government of Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश सरकार

E) Government of Telangana / तेलंगाना सरकार

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- State Bank of India signed an MoU with the Government of Tamil Nadu.
 - भारतीय स्टेट बैंक ने तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
 - The MoU aims to extend enhanced benefits under the Corporate Salary Package to employees of Tamil Nadu's State PSUs.
 - इस समझौते का उद्देश्य तमिलनाडु के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों को कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के तहत बेहतर लाभ प्रदान करना है।
 - The package includes zero-balance salary accounts. It also offers concessional interest rates on home, car and personal loans, along with waiver of processing fees on select services.
 - पैकेज में शून्य हैं। शामिल खाते सैलरी बैलेंस-इसके तहत गृह, कार और व्यक्तिगत ऋणों पर रियायती ब्याज दरें तथा चयनित सेवाओं पर प्रोसेसिंग फीस में छूट दी जाएगी।
-

Ques: The Government of India is planning the merger of which two public sector banks?

भारत सरकार किन दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की योजना बना रही है?

- A) Punjab National Bank & Canara Bank / पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक
- B) Union Bank of India & Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया
- C) Bank of Baroda & Central Bank of India / बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- D) Indian Bank & UCO Bank / इंडियन बैंक और यूको बैंक
- E) SBI & Bank of Maharashtra / एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India is planning a merger between Union Bank of India and Bank of India as part of banking sector consolidation.
- भारत सरकार बैंकिंग क्षेत्र के समेकन के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के विलय की योजना बना रही है।
- The objective of the proposed merger is to strengthen Public Sector Banks (PSBs).
- प्रस्तावित विलय का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) को मजबूत करना है।
- The merger aims to improve operational efficiency, scale of operations, and overall financial capacity.
- इस कदम का लक्ष्य परिचालन दक्षता, संचालन के पैमाने और समग्र वित्तीय क्षमता को बढ़ाना है।
- Bank consolidation is viewed as a reform to create globally competitive and resilient banks.
- बैंक समेकन को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और मजबूत बैंक बनाने वाले सुधार के रूप में देखा जा रहा है।

Ques: What is one of the key objectives of the RBI's revised Priority Sector Lending (PSL) guidelines effective from April 1, 2025?

1 अप्रैल 2025 से प्रभावी RBI की संशोधित प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) गाइडलाइंस का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) To completely eliminate priority sector lending / प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को पूरी तरह समाप्त करना
- B) To ensure more effective delivery of bank credit to priority sectors / प्रायोरिटी सेक्टरों तक बैंक ऋण की अधिक प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करना
- C) To increase service charges on small PSL loans / छोटे PSL ऋणों पर सेवा शुल्क बढ़ाना
- D) To restrict lending to cooperative institutions / सहकारी संस्थानों को ऋण सीमित करना
- E) To allow multiple banks to claim the same PSL loan / एक ही PSL ऋण पर कई बैंकों को दावा करने की अनुमति देना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- RBI issued revised Priority Sector Lending guidelines to improve effective delivery of bank credit to priority sectors.
 - RBI ने प्रायोरिटी सेक्टरों तक बैंक ऋण की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संशोधित PSL दिशानिर्देश जारी किए हैं।
 - The new PSL guidelines will come into effect from April 1, 2025.
 - नई PSL गाइडलाइंस 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी।
 - RBI introduced external auditor certification to ensure that the same PSL loan is not claimed by more than one bank.
 - RBI ने यह सुनिश्चित करने के लिए बाहरी ऑडिटर प्रमाणन की व्यवस्था की है कि एक ही PSL ऋण पर एक से अधिक बैंक दावा न करें।
 - Loans given to the National Cooperative Development Corporation (NCDC) are now eligible for PSL, capped at 5% of a bank's total PSL.
 - नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) को दिए गए ऋण अब PSL के अंतर्गत आएंगे, जो बैंक के कुल PSL के 5% तक सीमित होंगे।
 - Banks cannot charge any type of fee on PSL loans up to ₹50,000.
 - ₹50,000 तक के PSL ऋणों पर बैंक किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं ले सकते।
 - Regional Rural Banks must achieve 75% PSL of ANBC, but lending to Medium Enterprises, Social Infrastructure and Renewable Energy together is capped at 15% of ANBC.
 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ANBC का 75% PSL हासिल करना होगा, लेकिन मध्यम उद्यम, सामाजिक अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा को मिलाकर 15% तक ही गिना जाएगा।
 - Under amended norms, PSL targets for Small Finance Banks and Urban Co-operative Banks have been reduced from 75% to 60% of ANBC.
 - संशोधित नियमों के तहत स्मॉल फाइनेंस बैंकों और अर्बन को का बैंकों ऑपरेटिव-PSL लक्ष्य 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है।
 - Co-lending for PSL is now permitted among Scheduled Commercial Banks themselves.
 - अब PSL के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बीच आपसी को गई दी अनुमति की लेंडिंग-है।
 - Loans to National Cooperative Development Corporation (NCDC) are now eligible for PSL, capped at 5% of the bank's total PSL.
 - नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनसीडीसी) को दिए गए ऋण अब पीएसएल के लिए पात्र हैं, जो बैंक के कुल पीएसएल के 5% तक सीमित है।
-

Ques: What was the credit-to-deposit (CD) ratio of Indian banks as of December 31, according to RBI data?

RBI के आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर तक भारतीय बैंकों का क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) अनुपात कितना रहा?

- A) 75.25%
- B) 78.60%
- C) 80.10%
- D) 81.75%
- E) 85.00%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Indian banks' credit-to-deposit (CD) ratio rose to an all-time high of 81.75% as of December 31, as per RBI data.
- RBI के आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर तक भारतीय बैंकों का क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) अनुपात रिकॉर्ड 81.75% तक पहुँच गया।
- A CD ratio of 81.75% means banks lend ₹81.75 for every ₹100 deposited.
- 81.75% के CD अनुपात का अर्थ है कि बैंक हर ₹100 जमा पर ₹81.75 का ऋण देते हैं।
- The record-high CD ratio indicates that bank credit growth is outpacing deposit growth.
- यह रिकॉर्ड CD अनुपात दर्शाता है कि बैंक ऋण की वृद्धि, जमाओं की वृद्धि से तेज़ है।
- In 2025, bank credit grew by 11.4%, while deposits increased by 10.1%.
- वर्ष 2025 में बैंक ऋण 11.4% बढ़ा, जबकि जमाओं में केवल 10.1% की वृद्धि हुई।
- Outstanding deposits were around ₹248.5 लाख करोड़, while outstanding credit stood at nearly ₹202 लाख करोड़.
- कुल बकाया जमाएँ लगभग ₹248.5 लाख करोड़ रहीं, जबकि कुल ऋण लगभग ₹202 लाख करोड़ तक पहुँच गया।